

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 193/2017

No. E/PC-VII/2016/Policy (Vol. II)

Kolkata, Dated: 20/12/2017

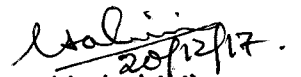
All Concerned

(as per standard list)

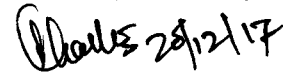
**Sub: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission -
Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey)
Allowance - Revision of Rates.**

The instructions of Ministry of Railways (Railway Board) issued vide their letter No. E(G)2017/AL 12-2 dated 12/12/2017 (PC-VII No.71, RBE No.156/2017) on the above noted subject are communicated herewith along with Hindi version, for information and necessary action. Board's earlier letters dated 14/11/08, dated 14/10/86 and dated 27/11/78 mentioned therein were circulated vide this office Serial nos. 155/2008, 158/1986 and letter no. E.67/0/1/Vol. IV dated 15/01/1979 respectively.

DA: As above.


(U. Lahiri)

Dy. Chief Personnel Officer/R
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone no.: 24103



**Index No. 1057: Revised rates of Project Allowance and Compensatory
(Construction/Survey) Allowance effective from 01/07/2017.**

(40), (41)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

**PC-VII.No.71/17
RBE NO.156/17**

No.E(G)2017/AL 12-2

Rail Bhawan, New Delhi, dt. 12.12.2017

**The General Manager, CAO(R),
All Zonal Railways & PUs
(as per mailing list)**

**Sub:- Recommendations of Seventh Central Pay Commission-
Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey)
Allowance-Revision of Rates**

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission circulated vide Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No.11-1/2016-1C dated 06/07/2017 and Office Memorandum No. 6/1/2017-E.II(B) dated 19.07.2017, the rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance have been revised w.e.f 01.07.2017.

2. Accordingly, the Ministry of Railways have considered the question of revision of rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance notified vide Board's letter No.E(G)2008/AL12-4 dated 14.11.2008 (Corresponding to MOF's O.M. No. 6(3)/2008-E.II.B dated 29.08.2008) and it has been decided with the approval of the Board that the rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance which have been covered in the Risk/Hardship Matrix, shall be revised as follows:

(a) Project Allowance

Level in Pay Matrix	Cell Name	Rate per month(Rs)
Level 9 and above	R3H2	3,400
Level 8 and below	R3H2	2,700

Note: i) The term 'Pay Level' in the revised pay structure means the 'Level' in the Pay Matrix.

Note: ii) Railway employees, whose offices are in the project area, but not specifically for the work of the project, and the projects are covered by the Ministry of Finance's O.M. No.20011/5/73-E.IV(B) dated 17.1.1975 on project allowance (circulated under Board's letter No.E(G)73AL12-27 dated 27.11.78 and No.PC-IV/86/Imp/AL-15 dated 14.10.86) shall, however be entitled to Project Allowance only at 50% of the above rates.

....2/

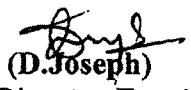
(b) **Compensatory (Construction/Survey) Allowance**

Level in Pay Matrix	Cell Name	Rate per month(Rs)
Level 9 and above	R3H2	3,400
Level 8 and below	R3H2	2,700

3. **Conditions:**

- (i) In respect of those employees who opt to continue in their pre-revised pay structure, corresponding Level in the Pay Matrix as indicated in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 would determine the allowance under these orders.
- (ii) These rates shall increase by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.
- (iii) All other terms and conditions governing the grant of these allowances shall remain unchanged.
- (iv) These orders shall take effect from 1st July 2017.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(D. Joseph)
Dy. Director Estt. (Genl.)
Railway Board.

No.E(G)2017/AL 12-2

Rail Bhawan, New Delhi, dt. 2-12-2017

1. PFA, All Indian Railways and Production Units.
2. Deputy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi..


FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

No.E(G)2017/AL 12-2

Rail Bhawan, New Delhi, dt. 2.12.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General, FROA.

...3/

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 71/17

आरबीई सं. 156/17

सं. ई(जी)2017/एएल 12-2

रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2017

महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - परियोजना भत्ता एवं क्षतिपूर्ति
(निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता की दरों में संशोधन।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 06/07/2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-1सी और दिनांक 19.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/2017-ई.॥बी) के तहत परिपत्रित किया गया था, के परिणामस्वरूप, परियोजना भत्ता और क्षतिपूर्ति (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता की दरों में 01.07.2017 से संशोधन किया गया है।

2. तदनुसार, रेल मंत्रालय ने परियोजना भत्ता और क्षतिपूर्ति (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता की दरों में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया है जिसे बोर्ड के दिनांक 14.11.2008 के पत्र सं. ई(जी)2008/एएल12-4 ((वित्त मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6(3)/2008-ई.॥बी के सदृश) के तहत अधिसूचित किया गया है और बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि परियोजना भत्ता और क्षतिपूर्ति (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ते की दरों, जिन्हें जोखिम/कठिनाई मैट्रिक्स में शामिल किया गया है, में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

(क) परियोजना भत्ता

पे मैट्रिक्स में लेवल	सेल का नाम	प्रति माह दर (रुपए में)
लेवल 9 और उससे ऊपर	आर3एच2	3,400
लेवल 8 और उससे नीचे	आर3एच2	2,700

नोट: i) संशोधित वेतन संरचना में 'वेतन लेवल' पद का तात्पर्य वेतन मैट्रिक्स में 'लेवल' से है।

नोट: ii) ऐसे रेल कर्मचारी जिनके कार्यालय परियोजना क्षेत्र में हैं, परन्तु वे खास तौर पर उस परियोजना के कार्य के लिए नहीं हैं और परियोजनाएं परियोजना भत्ता के आधार पर वित्त मंत्रालय के दिनांक 17.1.1975 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2011/5/73-ई.॥बी) (बोर्ड के

दिनांक 27.11.78 के पत्र सं. ई(जी)73एएल12-27 और दिनांक 14.10.86 के पत्र सं.पीसी-IV/86/इम्प/एएल-15 के तहत परिपत्रित) के तहत आती हैं, उपर्युक्त दरों के मात्र 50% पर परियोजना भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(ख) क्षतिपूर्ति (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता

पे मैट्रिक्स में लेवल	सेल का नाम	प्रति माह दर (रुपए में)
लेवल 9 और उससे ऊपर	आर3एच2	3,400
लेवल 8 और उससे नीचे	आर3एच2	2,700

3. शर्तें:

- (i) उन रेल कर्मचारियों जो अपने संशोधन पूर्व वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प देते हैं, के संबंध में पे मैट्रिक्स में तदनुरूपी लेवल, जैसाकि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में दर्शाया गया है, इन आदेशों के अंतर्गत भत्ते का निर्धारण करेगा।
- (ii) जब संशोधित वेतन संरचना में देय महंगाई भत्ते में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो इन दरों में 50% की वृद्धि हो जाएगी।
- (iii) इन भत्तों को विनियमित करने वाली अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- (iv) ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

डी जोसफ
(डी. जोसफ)
उप निदेशक स्था.(सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2017/एएल 12-2

रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2017

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली

सोनाली अर्जुन
कृते वित्त आयुक्त/रेलें